साप्ताहिक
डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21
RNI-MPHIN/2015/72544
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

जागत गांव हमार

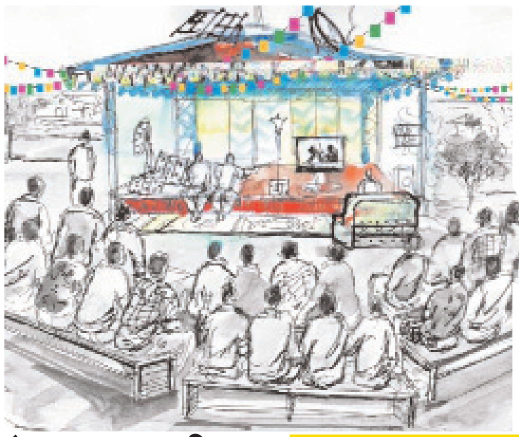

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 10-16 जनवरी 2022, अंक-41
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

प्रदेश में ओलावृष्टि से गेहूं, चना, अरहर और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता पहुंचाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। नुकसान का आकलन करने के बाद रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रदेश में गेहूं, सरसों, मसूर और धनिया की फसल बर्बाद

किसानों की उम्मीदों पर फिर गिरे ओले

- » 18 जिलों में 400 से ज्यादा गांवों में ओले से फसलें बर्बाद
- » अशोकनगर में 80 गांव में 10 हजार हेक्टेयर में धनिया की फसल हो गई खराब
- » रायसेन जिले में फसलों को 50 से 80 फीसदी तक हुआ
- » सिरोंज व लटेरी में 49 गांवों में 60 फीसदी फसलें खराब
- » विदिशा में 5 हजार हेक्टेयर जमीन में नुकसान हुआ

अरविंद मिश्र। भोपाल

प्रदेश में नए साल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। करीब दो दर्जन जिलों में ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। वहीं सरकार ने ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि सर्वे के आधार पर किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार नुकसान की भरपाई की जाएगी। इधर, गुना, राजगढ़, विदिशा, छिंदवाड़ा, सिवनी, सहित कई अन्य जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इससे गेहूं, सरसों, मसूर और धनिया की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गुना जिले के चांचौड़ा, आरोन और राघौगढ़ के करीब 100 गांवों में भारी ओलावृष्टि हुई है। चांचौड़ा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 51 गांव प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के प्रारंभिक आंकलन में 50 फीसदी तक नुकसान का दावा किया जा रहा है। जबकि मैदानी हालात बहुत खराब हैं। गई गांवों में पूरी फसल बर्बाद हो गई है। धनिया की फसल पूरी आड़ी हो गई। सरसों को भी भारी नुकसान हुआ है। राघौगढ़ के नारायणपुर के किसानों ने दावा किया है कि सरसों के पौधे कमर तक बढ़ गए थे, लेकिन ओलावृष्टि से सिर्फ ठंडल बचे हैं।

खेत पहुंचे राजगढ़ कलेक्टर

राजगढ़ जिले के उत्तरी भागों के करीब 30-40 गांवों में मध्यम आकार के ओले गिरे हैं। इससे सरसों और गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के पौधे टूकटकर खेतों में ही आड़े-तिरछे हो गए हैं। किसानों का कहना है कि 80 फीसदी तक फसलें बर्बाद हो गई हैं। भू-अभिलेख अधीक्षक संजय चौरसिया ने राजगढ़ व खिलचीपुर के पटवारियों से रिपोर्ट तलब की है। वहीं राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने छायन, पिपलोदी, देहरीनाथ सहित कई गांवों में पहुंचकर खुद नुकसान का मुआयना किया है।

विदिशा, सिरोंज में गिरे ओले

विदिशा जिले के लटेरी और सिरोंज के डेढ़ दर्जन से ज्यादा गांवों में ओले गिरने से किसानों की फसलें चौपट हो गईं। एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि लटेरी के राघौगढ़, उनारसी कलां, बाजना, भीला आदि दस गावों में ओले गिरे हैं। इनमें 5 गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। सिरोंज के ललितपुर, अमीरगढ़, हिनोतिया, बरखेड़ा नागन और मदागन में गांवों में ओले गिरे हैं।

सरकार ने दिए सर्वे का निर्देश

प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, सागर और भोपाल संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के आधार पर किसानों को फसल मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को राजस्व, कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों का संयुक्त दल बनाकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, सागर और ग्वालियर संभाग के कुछ जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। इससे मूंग, मसूर, चना, सरसों, आलू, टमाटर समेत अन्य बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। किसी भी किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। **-कमल पटेल, कृषि मंत्री**

- » किसान बोले-खेतों में बिछी फसल, 80 फीसदी तक हुआ फसल का नुकसान
- » गुना के 110, राजगढ़ 30 और विदिशा के 15 गांवों में सबसे ज्यादा टूटा कहर
- » ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का होगा सर्वे, किसानों को होगी नुकसान की भरपाई
- » सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को दल बनाकर सर्वे कराने के दिए निर्देश
- » डबरा में 12 गांव, भितरवार में 15 गांव की 3000 हेक्टेयर में फसल चौपट
- » भिंड के दबोह-आलमपुर के 20 गांवों में ओले गिरने से 70 फीसदी फसलें तबाह
- » दतिया के सेंवड़ा और भांडेर के 50 गांवों में 20 तक ओले गिरने से फसलों को नुकसान

पशु पालन एवं डेयरी व कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम की दो टूक

पशुओं की नस्ल सुधार पर हो काम और मप्र में बढ़ाएं शरबती गेहूं का रकबा

- » आत्मनिर्भर मप्र की राह में कोई रोड़ा बर्दास्त नहीं, लक्ष्य को समय में पूरा करें
- » नए साल में नए विजन के साथ सीएम ने अफसरों और मंत्रियों की ली क्लास

विशेष संवाददाता। भोपाल

नए साल में मप्र को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागों के मंत्री और अफसरों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि आत्मनिर्भर मप्र की राह में कोई रोड़ा बर्दास्त नहीं होगा। साथ ही केवल टारगेट पूरा करने से काम नहीं चलने वाला।

सभी विभाग अपने-अपने लक्ष्य को नियत समय में पूरा करें। वहीं पशु पालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए तेजी से प्रयास हों। पशुओं की नस्ल सुधारने से उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान ढंग से करें। मुख्यमंत्री ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। कम खर्च में बकरी पालन संभव है। नवीन चारा उत्पादन कार्यक्रम में चारे के अधिकाधिक उत्पादन के प्रयास हों। लोगों को पशुपालन से जोड़ने का कार्य हो। विशेषकर बैगा जनजाति को पशु देकर पशुपालन से जोड़ा जाए।

गौ-संवर्धन से रोजगार बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-संवर्धन से रोजगार को बढ़ाया जाए। पॉल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर आगे बढ़ाएं। भारत सरकार की बेकयार्ड योजना में चूजा प्रदाय का विस्तार किया जाए। मिशन मोड में लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास हों।

शरबती गेहूं का रकबा बढ़ाएं

इधर, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शरबती गेहूं मप्र की पहचान है। इसका क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास हों। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के साथ शुरू कराएं। इस दौरान कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और सभी जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने भंडारण प्र-संस्करण बुनियादी ढांचा विकास के लिए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। कस्टम, हायरिंग सेंटर में हम देश में नम्बर वन हैं। इनका संचालन ठीक ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के विभागीय विजन की जानकारी ली।

जैविक खेती में मप्र नंबर एक

सीएम शिवराज ने कहा कि फसल उत्पादन का आकलन और गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कार्य करें। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं हो। अगले साल के लिए भी अभी से प्लान कर लें। मांग आधारित कृषि को बढ़ावा दें। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। देश और धरती को बचाने के लिए जैविक खेती जरुरी है। जैविक खेती में मप्र देश में नंबर एक है। इसे बनाए रखने की जरुरत है। जैविक खेती का रकबा 17.31 लाख हैक्टेयर है। संभावनाओं का पता लगाकर निर्यात की ठोस रणनीति बनाएं। खेती को असली ताकत बनाना है।

पंच और सरपंच नहीं बन पाए 'परमेश्वर'

- » चुनाव तक सरपंच - पंच रहेंगे भूतपूर्व
- » सरकार ने फैसला पलटा, अधिकार छीने

भोपाल। मप्र सरकार ने पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान प्रशासकीय समिति से वापस ले ली है। दो दिन पहले ही समितियों को यह अधिकार दिए गए थे। इसमें सरपंचों को वित्तीय अधिकार भी दिए गए थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अपने फैसले को निरस्त कर दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद विभाग ने पंचायतों में कार्यों के संचालन के लिए प्रधान प्रशासकीय समिति की व्यवस्था लागू की थी। विभाग ने 4 जनवरी को आदेश जारी कर सरपंच व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन करने का अधिकार दिया गया था। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर भी यही व्यवस्था लागू की गई थी। प्रदेश में मार्च, 2020 में ही 22, 604 पंचायतों में सरपंच और पंच का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी तरह 841 जिला और 6774 जनपद पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नियमानुसार यहां चुनाव हो जाने चाहिए थे पर किसी न किसी कारण से ये टलते रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी में चुनाव कराने की तैयारी की थी, लेकिन ये भी नहीं हो पाए। आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है।

श्योपुर जिले में 319.38 करोड रुपए से बनेगा मूंझरी बांध

34 गांवों की कृषि भूमि को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी

मूंझरी बांध के लिए जारी हुए टेंडर, चार दशक पुरानी मांग

संवाददाता। श्योपुर

35 गांवों के किसानों का नवीन नहर का सपना सच होने के बाद अब मूंझरी बांध का सपना भी जल्द साकार होगा। ऐसा इसलिए कि मूंझरी बांध निर्माण के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा टेंडर जारी कर दिए गए है। 319 करोड़ 38 लाख से मूंझरी बांध का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण होने से 34 गांवों के किसानों की 11 हजार 575 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए बड़ौदा क्षेत्र के किसान मूंझरी बांध के टेंडर जारी होने से खुश नजर आ रहे है। उल्लेखनीय है कि बड़ौदा क्षेत्र में अहेली नदी पर मूंझरी नामक स्थान पर बांध का निर्माण कराए जाने की मांग क्षेत्र के किसान चार दशक से उठा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों की इस मांग के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी प्रयास किए। वहीं जल संसाधन विभाग के अफसरों ने कार्रवाई शुरू की। इसके बाद जल संसाधन विभाग श्योपुर के अधिकारियों ने मूंझरी बांध की डीपीआर बनाने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अक्टूबर 2019 में इसके टेंडर प्रकाशन के लिए फाइल प्रमुख अभियंता कार्यालय भोपाल भेज दी और शासन के द्वारा मूझरी बांध को स्वीकृति प्रदान की दी। गत 4 जनवरी को प्रमुख अभियंता कार्यालय के द्वारा मूंझरी बांध के लिए टेंडर भी जारी कर दिए है। टेंडर के मुताबिक मूंझरी बांध का निर्माण 319 करोड़ 38 लाख से किया जाएगा। उम्मीद है कि आगामी मार्च माह में मूंझरी बांध का निर्माण धरातल पर दिखने लग जाएगा।

आवदा से भी बड़ा होगा मूंझरी बांध

जल संसाधन विभाग के अफसरों के मुताबिक मूंझरी बांध जिले के आवदा बांध से बड़ा बनेगा। मूंझरी बांध से 34 गांवों की 11 हजार 575 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस बांध पर 319.38 करोड़ की राशि खर्च होगी। बांध का निर्माण तो 169 करोड़ से होगा। जबकि करीब 150 करोड़ से नहरी सिस्टम बिछाया जाएगा। पाइप सिस्टम के जरिए बांध का पानी सिंचाई के लिए खेतों में पहुंचेगा।

- मूंझरी बांध का निर्माण 319.38 करोड़ से होगा। इसके लिए टेंडर जारी हो गए है। इस बांध से सिंचाई के अलावा पेयजल के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

सुभाष गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग श्योपुर

- मूंझरी बांध के माध्यम से हजारों बीघा असिंचित जमीन को सिंचित किया जा सकेगा। परियोजना को शुरू कराने का श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जाता है।

दुर्गालाल विजय, पूर्व विधायक

बड़ौदा-श्योपुर की बुझेगी प्यास

319.38 करोड़ से बनकर तैयार होने वाला मूंझरी बांध जहां क्षेत्र के किसानों की भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएगा। वहीं बड़ौदा और श्योपुर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए पेयजल भी मुहैया कराएगा। क्योंकि इस बांध से श्योपुर और बड़ौदा को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध कराना शामिल है। जल संसाधन विभाग के अफसरों का कहना है कि श्योपुर और बड़ोदा में बांध से पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन तो दूसरा विभाग बिछाएगा, लेकिन पानी की उपलब्धता हमारा विभाग इस बांध के जरिए कराएगा।

किसान परीक्षण से जानेंगे मिट्टी की उर्वरता

खाद-बीज का समय पूर्व प्रबंधन खेती को बनाता है लाभकारी

अमजद खान। शाजापुर

ग्राम सोदनाखेड़ी में ग्राम सोदनाखेड़ी में किसान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। स्वाइल हेल्पकाई योजना अंतर्गत किसान चौपाल लगाकर कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को मिट्टी परीक्षण का महत्व बताया गया। संगोष्ठी में किसानों को जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र गिरवर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीआर अंबावतिया, कृषि वैज्ञानिक, डॉ. मुकेश सिंह, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मोहन बड़ोदिया वासुदेव पाटीदार, कार्यक्रम के संयोजक ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी सतीश चौधरी ने दी। विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खेती के बारे में, खेत की मिट्टी परीक्षण, कम समय में जैविक खाद बनाने की विधि, कम लागत में अच्छा उत्पादन करने के तरीके, बताते हुए कहा कि आज के युग में जैविक खेती का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कृषि की लागत कम की जाए, अधिक उत्पादन बढ़ाने पर जोर देते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि किसानों को मिट्टी परीक्षण का महत्व समझ कर अपने खेतों की मिट्टी को सबसे पहले प्रयोगशाला में टेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे खेत में कौन से खाद की कमी है। कौन से खाद ज्यादा मात्रा में उपयोग करना है। किस खाद का उपयोग ज्यादा नहीं करना है आदि जानकारियां हमें मिट्टी परीक्षण से ही मालूम होगा। आज के युग में किसान रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। जिससे कृषि और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमें जैविक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा तभी मिट्टी का और मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

जैविक खेती का पढ़ाया पाठ

कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि कई किसानों को अब भी जैविक खेती और कृषि के बारे में जानकारी नहीं है। कौन सी फसल कब लगाना है, किस खाद का प्रयोग कौन सी फसल में करना है। इस दौरान कृषि में लगने वाले रोगों और उनके उपचार की दवाइयों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। जमीन से लगने वाली प्रमुख बीमारियां, कीट नाशक दवाइयों के बारे में बताया गया। प्याज और लहसुन तथा आलू में लगने वाले कीड़ों की जानकारी एवं नियंत्रण की दवाइयां किसानों को बताई गई। अपने मोबाइल नंबर देकर किसानों को संपर्क में रहने की सलाह दी गई।

तभी खेती बनेगी लाभ का धंधा

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मोमन बड़ोदिया वासुदेव पाटीदार ने बताया कि किसानों को रसायनिक खादों की बजाए घर पर बनाए गए देशी खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाफेड गड्ढों में तैयार की गई खाद और गोबर गैस से निकलने वाली अवशिष्ट खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अच्छे बीजों का चयन कर, उपयुक्त समय पर किसानों को फसल की बोवनी करनी चाहिए। अच्छी तरीके से खाद और बीज का प्रबंध समय पूर्व कर लेना चाहिए, तभी किसानों को कृषि से अधिक लाभ होगा। कृषि लाभ का धंधा बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

उपार्जन केंद्र पर रखी फसल भी वापस होगी

भिंड में अब नहीं होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी

नीरज शर्मा। भिंड

अब जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर ज्वार, बाजरा और धान की खरीदी नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों से उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी की गई है। अब उन्हें भी फसल वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि उपार्जन समिति के सदस्यों के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में जिले के सभी किसानों की फसल को गुणवत्ताहीन मना गया है। इस स्थिति में अब किसानों को अपनी फसल औनेपौने दाम पर मजबूरी में बेचनी पड़ेगी।

सरकार के इस निर्णय से जिले के किसानों में निराशा है। वहीं अब किसान संगठन इस मुद्दे को लेकर 10 जनवरी को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने का इंतजार अब खत्म हो गया। जिले के किसान एक माह से खरीदी शुरू होने की राह देख रहे थे। गौरतलब है कि जिले में 22 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए 26 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। जिले में बाजरा, ज्वार और धान की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए जिलेभर के 13623 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिसमें से कुछ उपार्जन केंद्रों पर महज 674 किसानों से ही समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी कर उन्हें रसीद दे दी गई थी। 490 किसानों से उपार्जन केंद्र पर 22 हजार 823 क्विंटल बाजरा खरीदी गया था। वहीं 184 किसानों से 5503 क्विंटल ज्वार की खरीदी की गई थी। इसके बाद उपार्जन केंद्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए पहुंचने वाले किसानों की फसल को अमानक बताकर फसल की खरीदी बंद कर दी गई थी। इसके बाद उपार्जन केंद्र पर खरीदी गई फसल की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में खरीदी गई फसल को अमानक माना गया। इसलिए अब उपार्जन केंद्र पर जिन किसानों से फसल की खरीदी की गई थी, अब उन्हें फसल वापस की जाएगी।

13 हजार किसानों की फसल अमानक

जिले में समर्थन मूल्य पर फसल बेचे जाने के लिए 13623 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से महज 674 किसानों से उपार्जन केंद्र पर फसल की खरीदी की गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पंजीयन कराने वाले शेष 12949 किसानों की फसल की जब जांच ही नहीं की गई तो उनकी फसल को किस प्रकार से अमानक मान लिया गया। फसल की खरीदी न किए जाने के लिए गए निर्णय से किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश पनप रहा है।

तुलाई का खर्च किसानों की जेब पर

किसान अपनी फसल को बेचने के लिए किराया खर्च कर उपार्जन केंद्र पर पहुंचे थे, इसके बाद प्रति क्विंटल तुलाई का खर्च भी किसानों से वसूला गया। वहीं अब किसानों को उपार्जन केंद्र से अपनी फसल वापस ले जाने के लिए किराए में रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल तो खरीदी नहीं गई, उल्टा किसानों के जेब पर बोझ और बढ़ गया।

कलेक्टर ने लिखा था पत्र

अक्टूबर माह में हुई बारिश की वजह से बाजरे में नमी आ गई। इसके साथ ही कुछ किसानों के बाजरे का दाना काला पड़ गया। इस वजह से खरीद केंद्रों पर अपनी फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों फसल की खरीदी बंद कर दी गई थी। खरीदी बंद होने पर कलेक्टर ने प्रमुख सचिव खाद्य मप्र शासन भोपाल को पत्र लिखा था। किसानों को उम्मीद थी कि उपार्जन केंद्र दोबारा से शुरू होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं फसल खरीदना तो दूर जिन किसानों से उपार्जन केंद्र पर फसल की खरीदी गई गई। अब उन्हें भी फसल वापस दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।

- इसी तरह से वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार में भी किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी नहीं की गई थी। सरकार चाहती ही नहीं है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी की जाए। इसलिए जान बूझकर किसानों की फसल को अमानक बताया जा रहा है।

संजीव बरुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान संघर्ष एवं विकास संघ

- किसानों से अब समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी नहीं की जाएगी। साथ ही उपार्जन केंद्र पर जिन किसानों से फसल की खरीदी की गई है। उनकी फसल के सैंपल भी फेल हो गए हैं। इसलिए किसानों को फसल वापस की जाएगी।

अवधेश पांडेय, नागरिक आपूर्ति निगम भिंड

-मुख्यमंत्री ने की सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा, बोले

-बेस्ट प्रेक्टिसेज भी अपनाएं और आईटी निवेश नीति पर कठोर अमल हो

-भू-माफिया किसी का प्लाट न हड़पें, सहकारिता विभाग न्याय दिलवाए

नवाचार में हो सहकारिता

सिंगल सिटीजन डाटाबेस का लाभ अधिक से अधिक नागरिकों को मिले

प्रदेश के सघन वन क्षेत्रों को बढ़ाने में जन-सहयोग की अहम भूमिका

विशेष संवाददाता। भोपाल

गैर पारम्परिक क्षेत्रों में सहकारिता के उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण परिवहन सेवा, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहकारिता का अच्छा उपयोग हो सकता है। विभाग में कम्प्यूटर के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने का कार्य भी निरंतर किया जाए। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सक्षम बनाने अभियान को भी गति देना जरूरी है। यह समितियां सहकारिता को बढ़ाने का आधार हैं। इनसे जुड़े कर्मचारियों को उपयोगी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश में सहकार से समृद्धि के भाव को अंगीकार कर नवीन सहकारी नीति तैयार की जाए। जिन जिला सहकारी बैंकों का परफार्मेंस बेहतर नहीं है, उन्हें निरंतर शासकीय अंशपूंजी देने का औचित्य नहीं है। अन्य राज्यों के सहकारी क्षेत्र में हुए अच्छे कार्यों का मध्यप्रदेश में भी अनुसरण किया जाए।

सहकारिता का हो उपयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के साथ ही नए-नए क्षेत्रों में सहकारिता का उपयोग किया जाए। मत्स्य पालन, बकरी पालन, ग्रामीण परिवहन सेवा, हेल्थ सेक्टर, पर्यटन, विभिन्न खाद्य उत्पादों के प्र-संस्करण कार्य में सहकारिता से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। सहकारिता के पहुंच और उसके व्यापक प्रभाव को समझते हुए इसके लिए रोडमैप तैयार करें।

पीड़ित को दिलाएं न्याय

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं पर नियंत्रण हुआ है। लेकिन इसके लिए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति का निर्माण किया जाए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के जीवनभर की परिश्रम से अर्जित पूंजी व्यर्थ न जाए। ऐसे प्रकरणों में विभाग स्तर पर होने वाली कार्रवाई में यदि कोई वैधानिक अड़चनें हों, तो उसका रास्ता भी निकाला जाए। सहकारिता विभाग प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से पीड़ित और परेशान नागरिकों को न्याय दिलवाए।

विभाग के प्रयास

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण और किसानों को उनके द्वारा किए गए उत्पादन की अधिकतम कीमत दिलवाने के लिए अधो-संरचनात्मक विकास के कार्य किए गए हैं। एग्री इन्फ्रा फंड में 124 पैक्स में ग्रेडिंग सार्टिंग यूनिट स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार) में 107 करोड़ की लागत से 145 गोदाम मंजूर किए गए हैं। मनरेगा में 314 प्लेटफार्म निर्मित कर लिए गए हैं। इसके अलावा 797 प्लेटफार्म निर्माणाधीन हैं। विभाग और सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं की कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया गया है। ऑनलाइन सोसायटी पंजीयन पोर्टल प्रारंभ किया गया है। सहकारी बैंकों में नियुक्ति की कार्यवाही भी की जा रही है।

500 करोड़ का प्रावधान

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में गत वर्ष लगभग 30 लाख कृषक लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्त वर्ष में 13 हजार 707 करोड़ रुपए का ऋण वितरण गत 24 दिसंबर 2021 तक हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए 17 हजार करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। गत माह ही द्वितीय अनुपूरक अनुमान द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 500 करोड़ की शासकीय अंशपूंजी देने का प्रावधान किया गया है। मार्कफेड को इस राशि से उपार्जन और खाद व्यवसाय के लिए बिना ब्याज की राशि उपलब्ध हो जाने पर सुविधा होगी। इस दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव सहकारिता अजीत केसरी उपस्थित थे।

प्रदेश में बांस उत्पादन को दिया जाए बढ़ावा

इधर, वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बांस का उत्पादन बढ़ाया जाए। इससे लोगों को रोजगार के साथ प्रचुर मात्रा में लकड़ी भी मिल सकेगी। बांस का रकबा जितना बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाने के प्रयास हो। प्रदेश में सघन वन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इसमें जन-सहयोग की अहम भूमिका रही है। इस दौरान वन मंत्री विजय शाह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। इनके संरक्षण पर कोई कमी नहीं रहने दी जाए। सामुदायिक वन प्रबंधन के लिए निर्धारित संकल्प के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। कैंपा निधि का उपयोग बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर लें। ईको पर्यटन में रोजगार को बढ़ाया जाए।

वन पर्यटन को बढ़ाएं

वन पर्यटन अद्भुत कॉन्सेप्ट है। वन पर्यटन को अधिकाधिक बढ़ावा दिया जाए। वनों में पहुंचकर पर्यटक आनंद से भर जाते हैं। प्रदेश में बाघों के अलावा वन पर्यटन का सर्किट तैयार करने की कार्य-योजना बना ली जाए। नेशनल पार्क वन क्षेत्रों में ट्रेकिंग को बढ़ावा दें। टूरिज्म के साथ मिलकर कार्य करें। हमारे वन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाए।

ध्यान कुटी बनाई जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरकंटक सहित विभिन्न स्थानों पर ध्यान कुटी बनाई जा सकती हैं। लोगों को आनंद की चाह और ललक रहती है। 2500 वन समितियों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजनाएं लागू की जाएं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन सुरक्षा समितियों को लंबित लाभांश का भुगतान किया जाए। राजस्व और वन भूमि के विवादों का निराकरण तेजी से करें। पर्यावरणीय स्वीकृतियां समय पर जारी हो।

» मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान के बगीचों में भी अमरूद नहीं दिख रहे

» पहले फूल झड़े अब अमरूद फल छोटेपन में ही चटककर खराब हो रहा

मप्र में पैदावार 70 फीसद तक कम, अमरूद का फल भी देरी से पक रहा

मौसम और इल्ली की मार अमरूद की फसल बीमार

अवधेश दंडोतिया। मुरैना

चंबल संभाग के दो जिले मुरैना और श्योपुर में अमरूद (जामफल) की खेती बहुतायत में होती है। सैकड़ों किसानों की आमदनी के मुख्य जरिया अमरूद की खेती को मौसम की मार और बीमारी के वार ने चौपट कर दिया है। इस साल अमरूद की पैदावार 70 फीसद कम हो गई है, जो अमरूद पेड़ों में उगे वह समय पर पक नहीं रहे। पैदावार कम होने से किसानों की आय तीन गुना घट गई तो बाजार में अमरूद के दाम भी बीते साल की तुलना में महंगे हो गए हैं। गौरतलब है कि मुरैना जिले के जौरा, छैरा, अलापुर क्षेत्र में 650 बीघा और श्योपुर के सोईंकलां-ज्वालापुर क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन में अमरूद के बाग हैं। जौरा का अमरूद ग्वालियर-चंबल ही नहीं, बल्कि ग्वालियर, आगरा से लेकर दिल्ली तक ख्यात रखता है। उधर, श्योपुर के सोईंकलां-ज्वालापुर के ताइवानी पिंक एवं बर्फखान प्रजाति के अमरूद की मांग राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा और जयपुर तक है।

इस बार दूसरे शहरों में चंबल के अमरूद की सप्लाई नहीं हो पा रही। दूसरी ओर फल की पैदावार का आलम यह है कि पहले जिस पेड़ में 80 से 100 किलो तक अमरूद निकलता था, वह प्रति पेड़ 20 से 30 किलो की पैदावार रह गई। इससे किसानों की आमदनी ऐसी घटी कि सोईंकला में अमरूद के एक बीघा बाग का जो ठेका बीते साल एक लाख तक में गया, वह इस साल 25 से 38 हजार रुपए पर सिमट गया।

तीन गुना घटी आय

यानी किसान की आय तीन गुना तक कम हो गई। मुरैना के जौरा क्षेत्र में होने वाले अमरूद से जिला मुख्यालय से लेकर जौरा, कैलारस, सबलगढ़ के बाजारों में भरमार रहती थी। वहीं इस बार कहीं-कहीं अमरूद के हाथठेले या फुटपाथ किनारे दुकानें ही दिख रही हैं। आवक कम होने से अमरूद के दाम भी 40 से 50 रुपए किलो तक हैं, जो पिछले साल 30 रुपए किलो तक थे।

कृषि अनुसंधान केंद्र के बगीचे भी खाली

केवल किसान ही नहीं, मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि अनुसंधान केंद्र के 5 बीघा से ज्यादा बड़े बगीचों में खड़े अमरूद के पेड़ों में फल जहां-तहां नजर आ रहे हैं। अनुसंधान केंद्र के बगीचे में लखनऊ 49, ग्वालियर 24, ललित आदि वैरायटी के अमरूद होते हैं, जो मीठे और मुलायम होते हैं, लेकिन इस बार अनुसंधान केंद्र के बगीचे में भी 75 फीसद तक अमरूद कम आया है। यहां भी अमरूद समय पर नहीं पका। बड़े आकार के अमरूद में भी मिठास कम है। खाने में कड़क व कच्चापन है, फल के बीज इतने कड़क है कि दांतों से आसानी से नहीं फूटते। अधिकांश पेड़ों में अमरूद छोटेपन में ही चटककर, टूटकर जमीन पर गिर रहा है।

इस साल मानसून के अंत सीजन में लगातार बारिश हुई, उस समय अमरूद के पेड़ों में आया फूल झड़ गया। फूल कम होने से फल कम हुए, ऐसे में पेड़ की नई डालियां, पत्ते विकसित होने लगे। अमरूद पकने के लिए अधिकत तापमान 26 से ज्यादा और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री तक रहना चाहिए, लेकिन नवंबर महीने में जब अमरूद पकना शुरू होता है, तब तापमान कम हो गया। इस कारण फल अधपका सा रहने लगा।

डॉ. अशोक सिंह यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, मुरैना

पिछले साल 10 बीघा अमरूद के खेत का ठेका 10 लाख रुपए में गया था, इस बार यह बगीचे मात्र 1 लाख रुपए में ठेके पर गए हैं। जिस पेड़ में 100 किलो से ज्यादा फल पिछले साल टूटा था उसमें अबकी बार 25 से 30 किलो की पैदावार है। पेड़-फल पर इल्ली का प्रकोप है, जिस कारण फल कच्चा रह रहा है। फल की चमक भी कमजोर होने से बड़े शहरों में खपत नहीं हो रही।

सलीम खान किसान, ज्वालापुर, श्योपुर

अमरूद की फसल से सालभर का खर्च निकल आता था, लेकिन इस बार तो अमरूद की खेती में हुआ खर्च तक निकलना मुश्किल है। अमरूद के खेतों में दूसरी फसल हो नहीं सकती। पहले फूल झड़े तो लगा कि दोबारा आ जाएंगे। कृषि विभाग से कोई देखने तक नहीं आता, कोई सलाह, खाद-दवा अगर समय पर मिल जाती तो शायद फलों की पैदावार बढ़ जाती।

पप्पू कुशवाह किसान, जौरा, मुरैना

सार्थकता सिद्ध करते कृषि विज्ञान केंद्र

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

शुरुआत से अब तक के 46 वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र अपनी शैशवावस्था से किशोरावस्था और अब जवानी तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन यह अंतिम पड़ाव नहीं है। किसी भी प्राणी की यौवनावस्था सबसे ज्यादा ऊर्जावान एवं क्षमता से परिपूर्ण जरूर होती है, लेकिन इसके बाद का सारा जीवन गुणवत्ता, अनुभव, सोच की दूरदृष्टि आदि सब मिलकर एक मील के पत्थर का कार्य करता है। केवीके अभी यौवनावस्था में हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत ही है, पूरा जीवन बाकी है। इससे इतना तय है कि आने वाले समय में केवीके अपने नाम के अनुरूप साल दर साल वैज्ञानिकों-कर्मचारियों की मेहनत से गांव-किसानों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए देश के कृषि तकनीकी विकास को और अधिक ऊचांइयों तक ले जाएंगे।

भारतीय कृषि हमेशा से पूर्णतः मौसम पर आधारित रही है। गांवों में प्राचीन समय से ही एक कहावत प्रचलन में रही है, कि खेती करना किसानों के लिए किसी जुआ खेलने से कम नहीं है। 1960 के दशक के बाद आई हरित क्रांति के उपरांत भी पूरे देश में एक समान खेती के विकास का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा, नई दिल्ली के विभिन्न शोध संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा खेती-बाड़ी और उससे जुड़े विषयों पर किए जा रहे नए शोध इस दौर के बाद भी गांव, खेतों और किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। खेती-किसानी का ज्ञान प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों से निकलकर गावं-किसानों तक कैसे पहुंचे इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। इसी को मध्येनजर रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों को खोलने का अभिनव प्रयोग किया गया। इसकी शुरुआत पहला केवीके 1974 में पांडुचेरी में डॉ. मनमोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में गठित दल की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया। तब से अब तक 46 वर्षों के कालाखंड में देश के लगभग हर छोटे-बड़े जिलों में केवीके खोले जा चुके हैं। देश के कुछ बड़े जिलों में एक की बजाए दो केवीके खोले गए हैं। इस समय सम्पूर्ण देश में लगभग 722 केवीके कार्य कर रहे हैं। यह सभी केवीके पूरे भारत में संचालित 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। अटारी के नाम से लोकप्रिय यह संस्थान लुधियाना, जोधपुर, कानपुर, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, बारापानी, पुणे, मध्यप्रदेश के जबलपुर, हैदराबाद और बेंगलुरू में स्थापित हैं, जो कि केवीके के साथ समन्वय और निगरानी की भूमिका निभा रहे हैं। शुरुआती दौर में एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने वाले केवीके आज तकनीकी के परीक्षण, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, प्रसार के अलावा नित्रोज अनेकों कार्यक्रमों को संचालित करने का सफल कार्य कर रहे हैं। केवीके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं, जो कि कृषि प्रौद्योगिकी के ज्ञान और संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोध और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि और संबद्ध विषयों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है। किसानों को तकनीकी से रूबरू कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रमुख रूप से विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत कृषि प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता का आंकलन करने के लिए ऑन फॉर्म परीक्षण किए जाते हैं। किसानों के खेतों में प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन करना। आधुनिक वैज्ञानिक कृषि प्रौद्योगिकियों पर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए किसानों और विस्तार कर्मियों का क्षमता विकास करना। जिले की कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र की पहल का समर्थन करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के ज्ञान और संसाधन केंद्र के रूप में काम करना है। किसानों की रुचि के विभिन्न विषयों पर आईसीटी और अन्य मीडिया माध्यमों का उपयोग करते हुए कृषि परामर्श प्रदान करने के अलावा गुणवत्तापूर्ण तकनीकी का उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराना है। केवीके द्वारा अग्रिम पंक्ति की विस्तार गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही कृषि नवाचारों को पहचान कर उनका दस्तावेजीकरण को भी बढ़ावा दिया जाता है। केवीके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली द्वारा पूर्णतः वित्त पौषित प्लान टू प्लान संचालित परियोजना है। वर्तमान में केवीके प्रशासनिक दृष्टिकोण से आईसीएआर संस्थानों, राज्य एवं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, एनजीओ, राज्य सरकारों, अन्य शिक्षण संस्थानों आदि के अधीन पूरे देश में संचालित हो रहे हैं। जिसमें वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों एवं कर्मचारियों की नियुक्त से लेकर प्रशासनिक अधिकार इन संस्थानों का ही रहता है। सम्पूर्ण देश में इस समय कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन 472, केंद्रीय कृषि विवि द्वारा 22, आईसीएआर संस्थानों द्वारा 66, गैर सरकारी संगठनों द्वारा 104, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा 03, राज्य सरकारों द्वारा 38, केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा 03, डीम्ड विश्वद्यिालयों द्वारा 08 एवं अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा 05 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व में नवीनतम कृषि तकनीकी को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की यह एकमात्र और अनूठी परियोजना है। केवीके आज पूरे देश में अपनी अलग ही पहचान कायम कर चुके हैं। देश के हर जिले में केवीके आज फ्रंटलाइन एक्सटेंशन के अग्रणी पुरोधा बनके उभरे हैं। इन केंद्रों द्वारा अनिवार्य लक्ष्य के इतर दर्जनों प्रमुख कार्यक्रमों के साथ कई सारी परियोजनाओं का संचालन किसान, ग्रामीण युवक-युवतियों, पशुपालकों, कृषि उद्यमियों आदि के लिए किया जा रहा है। केवीके की द्वारा दी जा रही तकनीकी के प्रसार का ही प्रभाव है कि उन्नत तकनीकी आज गांव-गांव किसानों तक पहुंच सकी है। किसान परंपरागत खेती-बाड़ी से निकलकर वैज्ञानिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बेराजगार किसान युवक-युवतियां आदि उद्यानिकी, डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन से लेकर मछली पालन की ओर उन्मुख हुए हैं। किसानों में जैविक खेती की ओर भी रुझान तेजी बढ़ रहा है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा जारी एक हॉलिया रिपोर्ट में बताया गया कि देश में केवीके के प्रयासों से 3568 रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त शुद्ध कृषि आय बढ़ी है। इन केंद्रों द्वारा दी जा रही तकनीकी को अपनाने से एक रुपए के निवेश से किसानों को इसका 8 गुना तक लाभ मिला है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जिन क्षेत्रों के किसान केवीके के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। उन क्षेत्रों में खेती में गुणात्मक लाभ हुआ है। एक प्रशिक्षित किसान 30 अन्य साथी किसानों तक ज्ञान का प्रसार कर रहा है। यही कारण है कि केवीके द्वारा किसानों तक खेती की नई तकनीकी व वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाने से कृषि उत्पादकता को कई गुना तक बढ़ाने में मदद मिली है। केवीके के कार्यों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढ़ग से लागू करवाने में वर्तमान केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वंय केवीके के कार्यों को अधिक गतिशील बनाने में व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेने के कारण आज ये केंद्र अनेकों कार्यों को संपादित कर रहे हैं। आईसीएआर के माध्यम से आज केवीके भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की कार्य योजनाओं की सूची में नंबर एक पर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समय-समय पर केवीके की समीक्षा करते हुए इन केंद्रों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सदैव तत्पर रहे हैं। इसी तरह मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि स्वयं एक किसान हैं, वो भी सदैव किसानों को उच्चतम तकनीकी पहुंचे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर हैं। यही कारण है कि आज जिला स्तर से लेकर राज्य और केंद्र स्तर तक हर कोई केवीके की ओर देख रहा है। केवीके के द्वारा गांव-किसानों के कल्याण में दी जा रही कृषि तकनीकी को और अधिक प्रभावी बनाया सकता है।

फॉस्फेट विलेय-जैव उर्वरक फसलों के लिए वरदान

आशुतोष मिश्र
मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, कृषि संकाय, म.गॉ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना, म.प्र.

पौधों के वृद्धि विकास और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस पौधों व सूक्ष्म जीवों के लिए दूसरा महत्व पूर्ण पोषक तत्व होता है। मृदा में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध एवं जैविक कृषि में उपयोग की गई विभिन्न कार्बनिक खादों से फॉस्फोरस और कृत्रिम रूप से दी गई फॉस्फोरस की कुल मात्रा का 10-35 प्रतिशत भाग ही पौधे अवशोषित कर पाते हैं। शेष भाग मृदा में अघुलन शील अवस्था में पड़ा रहता है।

फॉस्फोरस घोलक जैव उर्वरक में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवियों का संग्रह रहता है जो मृदा में उपस्थित अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील एवं पौधों को उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। प्रमुख फॉस्फोरस विलायक सूक्ष्म जीव इस प्रकारहै। वैक्टीरिया-जैसे स्यूडोमानास स्ट्रेइटा, बैसिलस पोलीमाइंसा, बैसिलास मेगाटेरियम फंजाई जैसे एस्परजिलस अवामोरी, एस्परजिलस नाइगर आदि ये सूक्ष्म जीवाणु रॉक फॉस्फेट के साथ मृदा में स्थिर फॉस्फोरस को विलेय अवस्था में बदलते हैं, जबकि बैसिलस मेगाटोरियम जीवाणु स्थिर फॉस्फोरस के साथ-साथ कार्बनिक फॉस्फोरस को भी विलेय अवस्था में बदलता है। फॉस्फोरस विलयकारी जीवाणु अधिकाशतः विषम पोषित होते हैं, जो जैव पदार्थों का बर्धन करते हैं। इस क्रिया के दौरान कुछ कार्बनिक अम्ल जैसे कि मौलिक अम्ल, सम्सीनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल एवं फ्यूमेरिक अम्ल आदि बनाते हैं, जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आयरन या एल्यूमिनियम फॉस्फेट को विलय करते हैं। पीएसवी शीघ्र पौधे के जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है। बायोनिम्स फॉस्फोरस घोलक जीवाणु का उपयोग 8-10 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। बीज उपचार के लिए- 250 ग्रा/10 किग्रा बीज के लिए पर्याप्त होता है। पौध उपचार- 250 ग्रा प्रति एकड़ में उपयोग के लिए पौधे के लिए उपयोग विधि इस प्रकार है-जैसे बीजों के उपचार के लिए 250 ग्राम के कल्चर पैकेट को 250-500 मिली पानी में डालकर गाढ़ा घोल बनाते हैं। यह घोल 10 से 15 किग्रा बीच के लिए पर्याप्त होता है। इस घोल को बीजों के ऊपर डालकर अच्छी तरह तब तक मिलाते हैं जब तक कि बीजों के ऊपर जैव उर्वरकों का अच्छी परत न चढ़ जाए। उपचारित बीज को छायादार स्थानों पर सुखाकर तुरन्त बोवनी कर देना चाहिए। पौध जड़ उपचार के लिए 1-2 किग्रा कल्चर को 10-15 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-15 किग्रा बीजों से तैयार पौधे की जड़ों को 20-30 मिनट तक डुबाने के बाद तुरन्त रोपाई कर देना चाहिए। यह विधि रोपाई वाली फसलों के लिए होती है। मृदा उपचार- के लिए 8-10 किग्रा के कल्चर पैकेट को मिट्टी एवं कम्पोस्ट की बराबर मात्रा में मिश्रण तैयार करके बोवनी के समय या 24 घंटे पूर्व प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में छिड़क दे। यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो कल्चर के छिड़काव के तुरन्त बाद सिंचाई कर देना चाहिए। इनके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-प्रभावी पीएसवी (फॉस्फोरस घोलक जीवाणु) उपयोग करने से फॉस्फोरस का उपलब्ध्ता स्तर बढ़ता है। पौधों की जड़ों एवं तनों का विकास तेजी से होता है। पीएसवी के उपयोग से बीजों का अंकुरण तेज होता है। पीएसवी कल्चर के उपयोग से 10-20 प्रतिशत तक फसल उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। पीएसवी वृद्धि बर्धक हार्मोस जैसे आईएए और जीए का उत्पादन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि एवं विकास अच्छा होता है। पीएसवी के उपयोग से 25-30 किग्रा फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। पीएसवी प्रदूषण एवं विष रहित पर्यावरण को बनाए रखने में सहायक होता है। यह वायु मंडलीय नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु जैसे राइजोवियम, एजोस्पाइरिलम एवं एजोटोवैक्टर आदि की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। यह सभी फसलों में उपयोग किए जा सकते हैं। सस्ता एवं सुलभ है। उपयोग विधि आसान है। सूर्य की रोशनी व आग से दूर रखें। रोगाणु एवं कीटाणु नाशक तथा रासायनिक उर्वरकों को सम्पर्क में न रखें। छायादार एवं ठंडे स्थान में भंडारण न करें। अंतिम तिथि के पहले उपयोग कर लें। यदि राइजोवियम, एजोटोवैम्टर या एजोस्पीरिलम के साथ पीएसवी का उपयोग करना है, तो इसकी दोगनी मात्रा कर देनी चाहिए। कटे-फटे पैकटों का उपयोग न करें। इस प्रकार जैविक कृषि के फसल प्रबंधन में फॉस्फेट घोलिका जीवाणु उर्वरक की अहम भूमिका होती है।

जीरो बजट खेती से कृषि क्षेत्र को नया जीवन देने की तैयारी

बीते कुछ दशक में देश में किसानों की संख्या घटी है, लेकिन आज भी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। केंद्र किसानों के कल्याण के कई योजनाएं चला रहा है। 2021 दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में किसानों की स्थिति और आय बेहतर करने के लिए जीरो बजट खेती का फॉर्मूला सुझाया है। इसके तहत प्राकृतिक तरीके से इस प्रकार खेती को बढ़ावा दिया जाएगा कि किसानों की रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता और खर्च कम हो जाए। 2022 में जीरो बजट खेती पर तेज गति से कदम बढ़ाए जाने की उम्मीद है। पीएम ने प्रयोगशाला से सीधे खेत तक कृषि अनुसंधान का लाभ पहुंचाने की बात भी कही। इसके अंतर्गत ग्राम्य क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, रूरल मार्ट बनाने के साथ स्कूलों को भी नया रूप दिया जा रहा है। 27 हजार करोड़ से अधिक का बजट इस योजना में आवंटित किया गया है। देश में इसके तहत 76,207 कार्य होने हैं जिसमें से 31 हजार से अधिक पूर्ण किए जा चुके हैं। 14 हजार से अधिक पर काम जारी है और इस वर्ष पूर्ण होने की उम्मीद है। योजना में कामों की जियोटैगिंग भी की जा रही है। 44 हजार से अधिक कार्य जियोटैग हो चुके हैं। महामारी काल में देश की करीब 80 करोड़ जनता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन की व्यवस्था पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में की गई। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 तक यह योजना बढ़ा दी है। अब इसके अंतर्गत गरीब-वंचितों को अनाज के अलावा खाद्य तेल और नमक भी सरकार की तरफसे प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में लघु व मध्यम उद्योग है। छोटे व मंझोले उद्योगों को महामारी काल में सहायता के लिए केंद्र ने लोन देने की योजना शुरू की थी। 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत साढ़े नौ लाख करोड़ से अधिक की राशि लोन के रूप में उद्यमियों को दी गई। यह इसके पहले के वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक रही। इस वर्ष भी एमएसएमई सेक्टर के लिए यह सहायता संजीवनी की तरह होगी।

-देश की पिंक सिटी में मप्र के गुलाब की डिमांड

गुलाब की खेती से किसान की जिंदगी गुलजार

-जबलपुर में पॉलीहाउस में हो रही गुलाब की पैदावार

-किसान को प्रतिदिन सात से आठ हजार की कमाई

प्रवीन नामदेव | जबलपुर

परंपरा से हटकर खेती करना लाभ का धंधा बन सकता है। ये साबित किया है जबलपुर जिले के प्रगतिशील किसान संजय परोहा ने। पांच साल पहले जबलपुर मुख्यालय से 25 किमी दूर पहाड़ी खेड़ा में आधे एकड़ में पॉलीहाउस लगाकर गुलाब की खेती शुरू की थी। लॉकडाउन के दो सालों को छोड़ दें, तो वह रोज सात से आठ हजार रुपए के गुलाब बेचते हैं। चार से पांच स्थानीय लोगों को काम मिला है। उनके गुलाब की डिमांड जबलपुर के साथ लखनऊ, दिल्ली और जयपुर के बाजारों में काफी रहती है। पहाड़ीखेड़ा नाम के अनुरूप ही पहाड़ी वाला इलाका है। एक एकड़ के खेत में बड़े-बड़े पत्थरों में गुलाब की खेती लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। 2016 में जब यहां खेती के लिए जमीन की तैयारी शुरू कराई तो लोग हंसते थे। पहली वजह पानी की समस्या थी। यहां जलस्तर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मुझे 400 फीट गहराई में पानी मिल पाया। गुलाब के लिए लाल मिट्टी अच्छी मानी जाती है। उसे अलग से इस पहाड़ी खेत में डलवाया। पॉलीहाउस से लेकर गुलाब के 22 हजार पौधे लगाने में 40 लाख का प्रारंभिक खर्च आया था। इस तरह की खेती में हार्टीकल्चर विभाग से सब्सिडी के तौर पर मदद भी मिलती है।

पौधरोपण से पहले मिट्टी की तैयारी

पीली मिट्टी में पांच ट्राली गोबर की सड़ी खाद डलवा कर उसे अच्छे से मिक्सअप कराया था। साथ में इसमें 10 टन धान की भूसी मिलानी पड़ती है। रोटावेटर से जुताई कराकर खाद व भूसी को मिलाते हैं। फिर दो दिन उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद हल्का पानी डालकर वेड तैयार किया जाता है। ढाई फीट चौड़ाई और एक फीट ऊंचाई का वेड तैयार किया जाता है। बीच में एक फीट की दूरी रखी जाती है।

फंगस से बचाव जरूरी

पौधरोपण से पहले मिट्टी में फंगस अवरोधी, दीमक और चूहा दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। तीन से चार दिन बाद पौधरोपण करना पड़ता है। पौधों का चुनाव बेहद जरूरी है। बाजार में सबसे अधिक रेड गुलाब की डिमांड रहती है। आधे एकड़ के लिए मैने पुणे से टाटा स्टार रेड गुलाब के 22 हजार पौधे मंगवाए थे। प्रति पौधा 11 रुपए की दर से प्राप्त हुआ था। एक वेड पर दो लाइन गुलाब की जिग-जैग स्टाइल में 12 इंच की दूरी पर लगाना चाहिए। वेड में पौधे की सिंचाई के लिए दो लाइन ड्रिप पाइप और बीच में मिस्ट पाइप बिछाना पड़ता है।

75 दिन बाद से आने लगता है फूल

पौधरोपण के दूसरे दिन सिंचाई करनी होती है। सिंचाई के बाद ड्रिप से 19:19, क्लोरी-50, यूरिया, कैल्शियम, 0050, 13045 खाद देनी पड़ती है। पौधरोपण के ढाई महीने बाद से फूल आने लगता है। खाद के लिए ए-टैंक और बी-टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ए-टैंक से 0050 की 500 ग्राम, 19:19 की 750 ग्राम और यूरिया की 500 ग्राम मात्रा देनी पड़ती है। तीन दिन तक कोई खाद नहीं। बी-टैंक से कैल्शियम की 500 ग्राम व 13045 की 500 ग्राम मात्रा देनी चाहिए। फिर तीन दिन खाद नहीं देते। ए और बी टैंक का प्रयोग क्रमश: करना पड़ता है।

रोग से बचाव जरूरी

गुलाब के पौधे काफी नाजुक होते हैं। इसमें फफूंद जनित रोग, सफेद मकड़ी सहित कई रोग लगते हैं। ध्यान न दें, तो पूरा पौधा सूख सकता है।किसी भी पौधे में रोग के लक्षण दिखे, तो तुरंत उपचार करना चाहिए। इसके लिए जरूरी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए।

गुलाब के लिए सिंचाई अहम

गुलाब के पौधों की सिंचाई बेहद अहम है। इसके पौधों को न तो अधिक गीली मिट्टी होनी चाहिए न ही अधिक सूखा होना चाहिए। मिट्टी में नमी की मात्रा के अनुसार समय-समय पर सिंचाई करनी होती है। गर्मी के दिनों में फुहारा दस से 15 मिनट चलाकर तापमान नियंत्रित करना पड़ता है। गुलाब में फरवरी से जून तक सबसे अधिक फूल आते हैं। ठंड के दिनों में फूल की मात्रा कम हो जाती है।

फूल की कटिंग में सावधानी

गुलाब के फूलों की कटिंग में भी बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। इसे नीचे से तीन से चार पत्ती छोड़कर तना सहित काटना पड़ता है। जितना लंबा तना होता है, उसकी कीमत उतनी ही अधिक मिलती है। तीन से चार पत्ती छोड़ने का मतलब ये है कि वहां से गुलाब के नए तने निकलते हैं।

फूलों की खेती का वैल्यू एडीशन बढ़ाएगा किसानों की आय

भोपाल/नई दिल्ली। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फूलों की खेती जैसा वैल्यू एडिशन करना होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनाना चाहिए और प्रोसेसिंग से भी जुड़ना चाहिए। फूलों की आवश्यकता देश की परंपराओं, धार्मिक-सामाजिक-राजनीतिक आदि आयोजनों के अनुसार आज भी है। फूलों के व्यापार में निर्यात की दृष्टि से भी काफी गुंजाइश है। वहीं हमारे देश की विविध जलवायु इतनी समृद्ध है कि फूलों की खेती काफी फल-फूल सकती है। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुणे में भारतीय पुष्प अनुसंधान संस्थान में बुनियादी सुविधा के रूप में प्रक्षेत्र कार्यालय-सह-प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण के दौरान कही। उन्होंने किसानों को फूलों के मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे गुलाब में गुलकंद और अन्य फूलों के उत्पादों को समयानुरूप परिवर्तित करने व मार्केट बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। इनके साथ-साथ किसानों को तकनीकी रूप से भी सुदृढ़ होना होगा। फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने वेस्ट टू वैल्थ मिशन का जिक्र किया। साथ ही कहा कि कृष उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान के माध्यम से खेती को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि युवा इस ओर आकर्षित हों और नए रोजगार का सृजन हो सकें। नई किस्मों के विकास व अनुसंधान में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूलों की सुगंध कम नहीं हो, खुशबू का अपना ही महत्व है।

मुरैना में खेतों में बनाए 4 तालाबों में सहेजा बारिश का 15 करोड़ लीटर पानी

कंप्यूटर इंजीनियर बना किसान, पेश की मिसाल

फसलों की सिंचाई के साथ अब तालाबों में शुरू कर दिया मछली पालन भी

संवाददाता | मुरैना

उच्च शिक्षा के बाद हासिल की इंटरनेशनल कंपनी में 10 लाख रुपए पैकेज की नौकरी को छोड़ कम्प्यूटर इंजीनियर ने खेती का हाथ थाम लिया। इंजीनियर से किसान बने इस युवा ने फसलों की सिंचाई के लिए नहर-नदी, कुआं या बोरों पर निर्भरता खत्म करते हुए अनूठा तरीका अपनाया। खुद के खेत में चार बड़े-बड़े तालाब बनाए, जिनमें बारिश का पानी सहेजा। बारिश के पानी से लबाबल इन तालाबों से अब 60 बीघा खेतों की सिंचाई सालभर होती है। यह हाईटेक किसान हैं, मप्र के मुरैना जिले के प्रख्यात डॉ. रहे स्व. जितेंद्र चतुर्वेदी के बेटे गौरव चतुर्वेदी। गौरव को अफसर बनाने के लिए शुरू से ही अच्छे से अच्छे स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाया गया।

गौरव की स्कूली शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में हुई, इसके बाद 2004 में एमआईटीएस से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 2005 में एक इंटरनेशनल कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर बने। आज से 16 साल पहले 10 लाख रुपए सालाना के भारी-भरकम पैकेज पर दिल्ली में एक साल तक नौकरी की, लेकिन गौरव का रुझान खेती में कुछ नया करने का था। इसीलिए साल 2006 में नौकरी व दिल्ली छोड़कर वापस मुरैना आए और 60 बीघा खेतों में खेती की कमान संभाल ली। उन्होंने अपने खेतों में चार तालाब बनाए और इनमें बारिश का 15 करोड़ लीटर पानी सहेजा। इन तालाबों से न सिर्फ सर्दी के सीजन में गेहूं, सरसों, चना, अरहर बल्कि भीषण गर्मी के सीजन में भरपूर सिंचाई से होने वाली मूंग की खेती भी कर रहे हैं। एक बीघा जमीन में अमरूद व आंवला भी खेती के अलावा घर के उपयोग लिए जैविक सब्जियों की खेती भी इन्हीं तालाबों के पानी से हो रही है।

गौरव चतुर्वेदी ने 2006-07 में जब खेती संभाली तक उनके खेत में एक बोर था, जिससे 60 बीघा जमीन सिंचित नहीं हो पाती थी। गर्मी में बोर सूख जाता था। इसके बाद उन्होंने 2008 से 2016 के बीच एक-एक करके चार तालाब बनाए। इन तालाबों में जमा हुआ पानी के कारण भू-जल स्तर में ऐसा इजाफ हुआ, कि जो बोर गर्मी में दम तोड़ देता था उसमें 15 से 18 फीट जलस्तर बढ़ चुका है। चार तालाब बनने से सिंचाई पर होने वाला खर्च भी आधा हो गया है। खेतों के पास बने इन तालाबों से बिना बिजली के पाइप डालकर सिंचाई जो जाती है। इन तालाबों से सालभर सिंचाई के बाद अब आमदनी का दूसरा रास्ता निकालते हुए चारों तालाबों में मछली पालन भी शुरू कर दिया है।

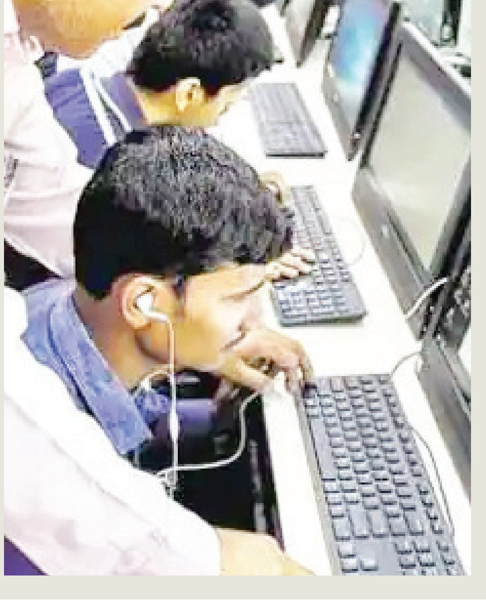

खेतों में बनाए तालाबों से फसलों की सिंचाई तो होती है। यह तरीका जल संरक्षण व भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी सबसे अधिक कारगर है। इसीलिए सरकार ने भी खेत तालाब योजना चलाई है, जिसके लिए किसानों को अनुदान मिलता है। इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती, मछली पालन करके भी किसानों की अतिरिक्त आय हो सकती है।

डॉ. संदीप तोमर, कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना

पहले एक बोर पर पूरी खेती निर्भर थी। कभी मोटर खराब होती, कभी बिजली गुल हो जाती, तो भी वाटर लेबल कम हो जाता। इस कारण खेती प्रभावित होती। 2008-09 में पहला तालाब बनाया, उससे सिंचाई इतनी आसान हो गई कि जहां-जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता था खेतों वहीं चार तालाब बना दिए। अब गर्मी में भी खेतों में फसल कर पाता हूं।

गौरव चतुर्वेदी, किसान व कंप्यूटर इंजीनियर

कृषि मंत्री के गृह जिले में परेशान किसान अब उखाड़कर फेंक रहे फसल

हरदा में चना की फसल में लगी फफूंद

संवाददाता। हरदा

प्रदेश के कृषिमंत्री के गृह जिला हरदा के कुछ ग्रामों में चना की फसल पर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। फफूंद, जड़ सड़न के कारण चना की फसल सूख रही है। इसके कारण किसान चना की फसल नष्ट करने के लिए बखरनी कर रहे हैं। इसके बाद गेहूं की बोवनी कर रहे हैं। इसके अलावा चने की फसल के सूखे पौधों को उखाड़कर फेंक भी रहे हैं। इधर, कृषि विभाग के अधिकारी एवं वैज्ञानिकों की टीम गांव में किसानों के खेतों की फसल का अवलोकन कर उक्त फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को उपाय बता रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में ग्राम कुकरावद, बूंदड़ा, सुखरास, बालागांव, झाड़पा, केलनपुर, कड़ाला उबारी एवं रेहटाखुर्द इत्यादि गांव के किसानों की फसल का मुआयना किया। इसमें कुछ किसानों के खेत में लगी चने की फसल में सूखा, जड़ सड़न फफूंद जनित रोग के लक्षण पाए गए।

रिकॉर्ड बोवनी

गौरतलब है कि जिले में 83 हजार 500 हेक्टेयर में चना एवं 1 लाख 6000 हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी की गई है। साथ ही सरसों, मसूर एवं अलसी की बोनी भी पूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार जिले में 1 लाख 91 हजार 800 हेक्टेयर बोवनी की गई है।

यह बताए गए किसानों को उपाय

कृषि विभाग के संयुक्त दल द्वारा किसानों को सुझाव दिया गया कि खेत में फसल चक्र (दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें) एवं गहरी जुताई की जाए। उक्त फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए टेबूकोनाजोल ट्राईफ्लोक्सिस्ट्रोबीन/ 100 ग्राम प्रति एकड़ एवं टेबूकोनाजोल सल्फर/400 ग्राम प्रति एकड़ में पावर स्प्रेयर से 125 लीटर एवं हाथपंप से 200 लीटर पानी की मात्रा का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव किया जाए।

किसान बखर रहे चने की फसल

चने की फसल में सूखा, जड़ सड़न और फफूंद जनित रोग से खराब हो रही फसल को किसानों ने बखरना शुरू कर दिया है। ग्राम डंडावा के किसान नेमीचंद्र पिता रामदयाल विश्नोई ने 8 एकड़ में लगी चना की फसल को बखरनी कर गेहूं की बोवनी की है। इसी प्रकार कुकरावद के किसान ओमकार टाले ने नौ एकड़ में लगी चना की फसल, खामापड़वा के किसान ने 7.5 एकड़, नीमाचा बारचा के किसान ने 3 एकड़ की फसल को बखरनी कर गेहूं की फसल बोई है। किसानों ने बताया कि चना की फसल के पौधे सूख रहे हैं।

कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग का संयुक्त दल किसानों के खेतों की फसल का अवलोकन कर रहा है। इस दौरान किसानों को चना की फसल में मिल रहे रोगों के नियंत्रण के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। किसानों को फसल में लग रहे रोगों के बारे में बताया जा रहा है।

एमपीएस चंद्रावत, उप संचालक, कृषि विभाग, हरदा

चने की फसल में सूखा जड़ सड़न फफूंद जनित रोग के लक्षण पाए गए। चने फसल में एस्कोकायटा ब्लाइट, स्कलेरोशिया तना सड़न, काली जड़ सड़न एवं सूखा जड़ सड़न आदि बीमारियों से संक्रमित हो रही है।

डॉ. ओमप्रकाश भारती, कृषि वैज्ञानिक, हरदा

खेती को लाभ का धंधा बनाने कृषि विभाग कर रहा नवाचार

विक्रेताओं ने देखी जैविक, प्राकृतिक-गौ आधारित खेती

मदन काबरा। धार/सुसारी

कृषि विज्ञान केंद्र धार ने जैविक व प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभों को किसानों तक तेजी से पहुंचाने के लिए एक नवाचार किया है। इसके तहत डिप्लोमा करने वाले जिले के 80 कृषि विपणन आदान-प्रदान विक्रेताओं को धरातल पर किस तरह जैविक खेती के साथ देशी प्राकृतिक खाद व कीटनाशक बनता है, उससे रूबरू कराया। इसके पीछे मकसद यह है कि कीटनाशक दवाई और किसानों के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी कीटनाशक आदान-प्रदान विक्रेता को जोड़ा जाए। इससे किसानों तक जैविक खेती के लाभ व हानि पहुंचे सके। निसरपुर ब्लॉक के आदर्श ग्राम नवादपुरा में जैविक, प्राकृतिक व गौ आधारित खेती हो रही है। इसके चलते आदान-प्रदान विक्रेताओं को भ्रमण कराया गया। निसरपुर ब्लॉक के नवाचारों के लिए प्रसिद्ध गांव नवादपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र धार के प्रमुख डॉ. केसी आसाठी, कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीएस गठिया, मृदा वैज्ञानिक डॉ. एसएस चौहान के साथ जिलेभर के 80 कृषि विपणन आदान-प्रदान व्यापारी पहुंचे थे। केंद्र सरकार के नियम के तहत कीटनाशक व खाद के विक्रेता इस कार्य का डिप्लोमा करने के बाद ही इन वस्तुओं का विक्रय कर सकेंगे।

जैविक खेती के लिए जोड़ना जरूरी

कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीएस गाठिया ने बताया कि रासायनिक व कीटनाशक को हम खेती में किस तरह कम कर सकते हैं। साथ ही जैविक व प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को इस ओर मोड़ने के लिए विभाग अपना कार्य कर रहा है। किसानों व विभाग के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कीटनाशक दवाइयों के विक्रेता हैं। ऐसे में उन्हें हम जब तक नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम जैविक व प्राकृतिक खेती को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हम इन विक्रेताओं को विभाग की ओर से डिप्लोमा के अध्ययन के दौरान जानकारी देते हैं, लेकिन अब हम इन्हें धरातल पर यह कैसे होता है, इसके क्या फायदे व हानि है, यह बता रहे हैं, ताकि ये लोग किसानों को बता पाएं। नवादपुरा में जैविक व प्राकृतिक खेती के साथ रासायनिक खाद व कीटनाशकों के विकल्पों को लेकर कार्य किया जा रहा है। यह हमें गांव के कमल पटेल व किसानों ने बताया।

ग्रामोदय विवि में भूमि सुपोषण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन

चित्रकूट। भूमि सुपोषण विषय को लेकर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विवि के सीएमसीएलडीपी सभागार में नाबार्ड सतना के डीडीएम इलीसियस कुजूर ने किया। अध्यक्षता कुलपति प्रो. भरत मिश्रा ने की। **भूमि सुपोषण**: एप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेज टु इनरिच सॉइल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर सस्टेनबल रूरल डेवलपमेंट विषयक दो दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि फेंस संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री गोलोक बिहारी राय और नाबार्ड रीवा के डीडीएम सुनील पीढ़िकले रहे। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे कुलपति ने कहा कि भूमि पोषण की परंपरा सदैव से हम अपनाते आ रहे हैं। कृषि और पशुपालन वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे नवीन खोजों के इसके महत्व को और भी स्वीकार किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि विवि के प्राध्यापकों ने भूमि सुपोषण के विभिन्न आयामों पर देश के विद्वानों और प्राध्यापकों को बुलाकर विचार मंथन और शोध प्रस्तुति का विशिष्ट कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यादायिनी मां सरस्वती एवं भारतरत्न राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। पारंपरिक स्वागत भाषण कृषि संकाय के अधिष्ठाता एवं आयोजन अध्यक्ष प्रो देव प्रभाकर राय ने प्रस्तुत किया। कीनोट प्रस्तुति नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के प्राध्यापक डॉ. अंजनी कुमार मिश्रा ने की। धन्यवाद ज्ञापन आयोजन सचिव एवं पशुपालन प्राध्यापक डॉ. उमेश कुमार शुक्ला ने किया।

-रीवा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों किया फल का निरीक्षण और दी सलाह

उन्नत खेती के लिए किसान सुरक्षित तरीके से करें कीटनाशकों का इस्तेमाल

संवाददाता। रीवा

कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा द्वारा ग्राम खोखम में क्लस्टर एवं प्रक्षेत्र परीक्षण प्रदर्शन के अंतर्गत किसानों के खेत भ्रमण कर विभिन्न फसलों गेहूं, चना, अलसी, मसूर, सारसों का निरीक्षण किया। जिसमें केंद्र के पौध सरंक्षण वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार ने फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग के प्रबंधन के विषय में जैविक एवं रसायनिक विधियों को बताया और साथ में केंद्र की वैज्ञानिक डॉ. स्मिता सिंह ने फसलों में खरपतवार, खाद, सिंचाई प्रबंधन के विषय में जानकारी दिया। वहीं डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. संजय सिंह, संदीप शर्मा, डॉ. किंजल्क सिंह और डॉ. सीजे सिंह ने किसानों को सुरक्षित तरीके से कीटनाशकों के इस्तेमाल के बार में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कीटनाशक रासायनिक या जैविक पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है, जो कीड़े मकोड़ों से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने, उन्हें मारने या उनसे बचाने के लिए किया जाता है। उन्नत खेती के लिए कीटनाशकों

का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करना जरूरी है। कीटनाशक दवा हमेशा अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें, बिल आवश्यक रूप से लें। सुरक्षा की दृष्टि से कीटनाशक दवाओं को परिवहन से पहले अच्छी तरह पैक कर लें, रिसाव ना हो इसका ध्यान रखें। जिस कीटनाशक दवा पर पर्चा ना हो उसे ना खरीदें, सुनिश्चित कर लें कि दवा सील पैक है। उचित कीट नियंत्रण के लिए सही कीटनाशक का चुनाव करें।

घोल बताते समय रखें सावधानियां

कीटनाशक का घोल बताने समय हमेशा साफपानी का इस्तेमाल करें। कीटनाशक की बोतल को मुंह से नहीं खोलें। कीटनाशक का घोल बनाते समय दस्तानों का इस्तेमाल करें। साथ ही मुंह को कपड़े से ढकें। कीटनाशी के डब्बे पर लिखी सावधानियां अच्छे से पढ़ लें। जरूरत के अनुसार ही कीटनाशी का घोल बनाएं। कीटनाशी छिड़काव यंत्र को ना सूंघें। कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल नजदीकी क्षेत्र में कार्यरत सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक की सलाह लेकर ही करें। छिद्रित या टूटू-फूटे उपकरणों का प्रयोग घोल बनाने में न करें। कीटनाशी का घोल बनाते समय कुछ खाना-पीना, चबाना नहीं चाहिए और ना ही धूम्रपान करना चाहिए।

इस तरह करें छिड़काव

कीटनाशक का छिड़काव सुबह और शाम के समय ही करें। तपती गर्मी व तेज हवा चलने के दौरान कीटनाशी न छिड़कें। कीटनाशक का बारिश होने के पश्चात तथा बारिश होने के पूर्व छिड़काव न करें। छिड़काव करते ही खेत में मजदूरों तथा जावनरों का प्रवेश निषेध करें। छिड़काव करते समय हांथों में दस्ताने एवं मुंह पर कपड़ा बांध लें और आंखों के बचाव के लिए चश्मा पहनें।

भंडारण के समय सावधानियां

घरों में कीटनाशकों का भंडारण करने से बचें। कीटनाशक को कभी चारे या खाने योग्य वस्तुओं के साथ भंडारण न करें। कीटनाशक को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक का सूरज की रोशनी व बारिश से बचाव करें। कीटनाशक को खरपतवारनाशी के साथ नहीं रखें। कीटनाशी डिब्बों का उपयोग खाद्य पदार्थ और पानी के लिए न करें।

लाल टिपारा आदर्श गौशाला को पर्यटन केंद्र बनाने की कवायद, नगर निगम की आदर्श लाल टिपारा गौशाला बनेगी पर्यटन केंद्र

गोबर-गौ मूत्र से गोनाइल और गौअर्क से गौशाला होगी आत्मनिर्भर

यहां निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए शहर में लगेंगे स्टाल

दिव्या मिश्रा। ग्वालियर

नगर निगम ने लाल टिपारा आदर्श गौशाला को आत्मनिर्भर और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर ली है। इसके अंतर्गत गौशाला में ही गाय के गोबर व गौमूत्र से कई उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इनका विक्रय करने के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर स्टाल लगाए जाएंगे। इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए नगर निगम ने पर्यटन संस्थान के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर जल्द ही तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। निगर निगम की लाल टिपारा आदर्श गोशाला में 7000 गाय हैं, लेकिन इनके गोबर और मूत्र से अभी अधिक उत्पाद तैयार नहीं किए जा रहे हैं। निगम गाय के गोबर एवं मूत्र से निर्मित होने वाले उत्पादों को बनाने की तैयारी कर रहा है। गौमूत्र से गोनाइल बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक कीटाणुनाशक भी होते हैं। यह फिनाइल का कार्य करता है। इस गोनाइल को सभी शासकीय दफ्तरों में उपयोग के लिए दिया जाएगा।

आयुर्वेद में गौमूत्र का काफी महत्व है। इस गौअर्क को भी बाजार में बेचने के लिए भेजा जाएगा। गोबर से गौकाष्ठ बनाए जाएंगे, जिनसे सभी मुक्तिधामों में अंतिम संस्कार होगा। इससे पर्यावरण की रक्षा होगी, क्योंकि अभी एक अंतिम संस्कार में कंडों के साथ 300 से 400 किलो लकड़ी का उपयोग किया जाता है। निगमायुक्त का कहना है लाल टिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही गायों से मिलने वाले उत्पादों को भी बाजार में बिक्री के लिए जल्द ही रखा जाएगा।

गौशाला में यह उत्पाद भी बनाए जाएंगे

धूपबत्ती: गाय के गोबर से धूपबत्ती बनाई जाएगी। गोबर से बनी धूपबत्ती को मंदिर में जलाना काफी शुभ माना जाता है। यह धूपबत्ती पूरी तरह से प्राकृतिक होगी इसमें गाय का घी, गूगल, चंदन सहित अन्य कई प्रकार की जड़ीबूटिया मिलाई जाएंगी।

भगवान की मूर्तियां: गौशाला में नवरात्र और गणेशोत्सव के लिए मूर्तियां तैयार की जाएंगी। इन मूर्तियों को बनाने के लिए गोबर में चिकनी मिट्टी और प्राकृतिक गोंद को मिलाया जाता है। ऐसा करने से मूर्तियां विसर्जन के बाद आसानी से पानी में घुल जाती हैं और जलीय संपदा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है।

मिलेंगे खाद्य पदार्थ: गौशाला में आने वाले सैलानियों के लिए भोजन का इंतजाम किया जाएगा। पर्यटक चाहें तो गौशाला में बने भंडारे एवं गौमाता से मिलने वाले दूध, दही, मक्खन आदि से बने खाद्य पदार्थों का भोजन कर सकता है। गौशाला के अंदर ही होटलों के स्टाल भी खुलवाए जाएंगे, जिससे पर्यटक अपनी पसंद का भोजन कर सकेंगे।

नर्मदापुरम में जल संपदा का अकूत भंडार, -जल संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास हुए

जल संचय से किसान हो रहे आत्मनिर्भर

वर्ष के 12 महीने पानी की कमी नहीं होती

विजय कुंभारे। होशंगाबाद

नर्मदा, तवा, हथेड़, देनवा और दूधी सहित अनेक नदियों और तवा बांध होने से नर्मदापुरम जिले में जल संपदा का अकूत भंडार है। इसके साथ ही जिले में अनेक छोटे तलाब, बोरी बंधान बनाए जाने से जल संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास हुए हैं। जिससे यहां पर वर्ष के 12 माह पानी की कमी नहीं होती है। जल की भरपूर पूर्ति होने से रबी, खरीफ और तीसरी फसलों की पैदावार में जिले का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। बड़े ब्लाकों में जल की कमी नहीं है, इसलिए जल संचय की ज्यादा चिंता नहीं रहती है। इसी कारण जिले के बड़े ब्लाकों की तुलना में केसला तथा बनखेड़ी जैसे छोटे ब्लाकों में जल संरक्षण को लेकर बेहतर प्रयास हो रहे हैं। खेत तालाब योजना हो, बोरी बंधान हो या स्वयं के द्वारा छोटे तालाब खोदकर बारिश की बूंदों को सहेजने के कार्य हों, यहां काफी हो रहे हैं। जिससे आने वाले वर्षों में जमीनी जल स्तर बने रहने तथा जल की कमी नहीं रहेगी।

2200 करोड़ से बनेगा बांध

बनखेड़ी के भरावपड़ाव गांव में नर्मदा विकास प्राधिकरण के द्वारा 2185 करोड़ की राशि से बांध बनाने की स्वीकृति हुई है। बांध बनने से जिले के करीब 92 गांव में 40 हजार हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिंचित होगी। बांध नर्मदा विकास प्राधिकरण बनाएगा। बांध बनने से बनखेड़ी, पिपरिया के हजारों किसानों को फायदा होगा। जिले में अभी तीन लाख हेक्टेयर से ज्यादा में सिंचाई होती है।

बढ़ रहीं जल संरचनाएं

जिले में जलाभिषेकम से संबंधित जल संरचनाओं के तहत 510.98 लाख रुपए से 305 कार्य हुए हैं। पूर्व वर्षों में गर्मी के दिनों में पानी की कमी होने पर कई क्षेत्रों में परेशानी हो जाती थी। इस बार गर्मी में भी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र केसला सहित अन्य ब्लाकों में खेत तालाब, स्टाप डैम, कपिल धारा व सामुदायिक रूप से जल संरक्षण के अनेक कार्य हुए हैं।

कोराना काल में हुए बेहतर कार्य

कोरोना काल के दौरान मुख्य रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना से केसला सहित अन्य जनपद क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा, सामुदायिक निर्माण कार्य होने से बहुउद्देशीय कार्य हुए हैं। फसलों को पानी मिलना शुरू हुआ, सब्जी की पैदावार और मछली पालन तक होने लगा है।

जनपद पंचायत	निर्माण कार्यो की संख्या	स्वीकृत व लागत राशि
माखन नगर बाबई	53	57.88 लाख
बनखेड़ी	52	53.62 लाख
होशंगाबाद	05	11.43 लाख
केसला	58	117.76 लाख
पिपरिया	28	38.91लाख
सिवनी मालवा	39	64.9 लाख
सोहागपुर	39	58.10 लाख
योग	274	402 लाख

जिले में पानी की कमी बनी रहती थी। उन क्षेत्रों में शासन की योजना मनरेगा के माध्यम से खेत तालाब,स्टाप डैम, कपिल धारा, सामुदायिक कूप आदि के कार्य तेजी से हुए हैं जिससे जल संरक्षण के साथ ही खेती के कार्य के उपयोग के लिए जलाभिषेक के कार्य हुए हैं।
मनोज सरियाम, सीईओ जिला पंचायत, होशंगाबाद

बकरी पालन से किसानों की बढ़ रही आमदानी

संवाददाता। बड़वानी

जिले के सुदुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित पुजारिया फलिया ग्राम देरवालिया की महिला कृषक निरसा सस्ते पति फेंदा सिहं कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी की प्रगतिशील महिला कृषक हैं, जिन्होंने अपनी खेती के कार्य को बकरी पालन के साथ व्यवसायिक रूप में अपना कर अन्य ग्रामीणों में उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिससे ग्राम के अन्य महिला कृषक भी खेती के साथ-साथ बकरीपालन की ओर आकर्षित हो रही है। निरसा सस्ते विगत 3 वर्षो से कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी से जुड़कर वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कपास, चना, मक्का की खेती कर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। इनके व इनके पति के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र से बकरी पालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। इसके बाद वैज्ञानिकों से सलाह पर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए बकरी पालन का कार्य खेती से जोड़कर करना प्रारंभ किया। बकरी पालन की तकनीकी सलाह के लिए केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसके बड़ोदिया एवं रविन्द्र सिकरवार से सम्पर्क स्थापित कर लगातार मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। इनके द्वारा बकरीयों के खान-पान प्रबंधन के लिए एजोला की इकाई भी तैयार कर बकरियों, मुर्गियों एवं अन्य पशुओं को दाने एवं भूसे के साथ एजोला मिलाकर खाने के लिए दे रही है, जिससे बकरियों एवं अन्य पशुओं को विटामीन प्रोटीन और कई प्रकार के मिनरल्स मिलने से बढ़वार एवं वजन में वृद्धि हुई है। इनके द्वारा बकरी पालन से लगभग 55000 रुपए अतिरिक्त शुद्ध आय प्राप्त की है।

बकरी पालन में बड़वानी जिला आठवें नंबर पर

बकरियों को लोग अक्सर नकद पैसे देकर खरीदते हैं। यह कृषि आधारित व्यवसाय होने के साथ-साथ कम खर्चीला व्यवसाय है, जिससे अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। इस कार्य में उन्होंने अपने साथ-साथ ग्राम के अन्य कृषक महिला कृषकों को भी बकरीपालन करने की सलाह दी। निरसा सस्ते द्वारा वर्तमान में केन्द्र की बकरीपालन इकाई का भ्रमण के दौरान वैज्ञानिकों से सलाह प्राप्त कर सिरोही, जमनापारी, उस्मानाबादी और बीटल आदि उन्नत नस्ल की बकरीयों की जानकारी प्राप्त की और इसे भविष्य में इन द्विउदेश्यी नस्लों को अपनाकर और अधिक लाभ लेने की बात कही। केंद्र के डॉ. बड़ोदिया ने बताया कि बकरी पालन व्यवसाय जिले में तेजी से बढ़ रहा है। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश में आंठवा स्थान बकरी पालन में रखता है।

बागवानी फसलों से किसानों को मिलेगा डबल मुनाफा

पारंपरिक के मुकाबले बागवानी फसलों में अधिक होगी कमाई

मंत्री ने दी बागवानी फसलों की खेती करने की सलाह

विजय कुंभारे। होशंगाबाद

हार्टिकल्चर क्षेत्र में किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। संभाग स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनने पर किसान नई-नई तकनीकों की ट्रेनिंग लेकर अपनी आय को दोगुना करेंगे। यह बात मध्य प्रदेश के हॉर्टिकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने वो होशंगाबाद में 98 लाख की लागत से बनने वाले हार्टिकल्चर कृषक प्रशिक्षण केंद्र के भूमि-पूजन कार्यक्रम के दौरान कही। हॉर्टिकल्चर के लिए होशंगाबाद जिले में होशंगाबाद ब्लॉक का विशेष रूप से चयन किया गया है। कुशवाह ने कहा कि रबी और खरीफ फसलों के साथ हार्टिकल्चर के लिए भी भूमि का रकबा तय किया जाए। सब्जी, फल और मसालों की फसलों की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान हॉर्टिकल्चर (बागवानी फसलों) की ओर बढ़ेंगे तो उन्हें डबल मुनाफा मिलेगा। एक तो कम खाद लगेगी और फलों से भी लाभ मिलेगा। इसलिए किसानों को फलों और सब्जियों की खेती की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

अमरूद है होशंगाबाद का एक जिला-एक उत्पाद

मंत्री ने कहा कि विश्व बाजार भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। देश और प्रदेश से जैविक खेती और फलों की पैदावार की अधिक उम्मीदें हैं। प्रदेश के हर जिले में एक जिला-एक उत्पाद के तहत उत्पाद तय किए गए हैं। होशंगाबाद के लिए अमरूद को चुना गया है। कुशवाह ने किसानों का आह्वान किया कि वे फूड प्रोसेसिंग के लिए आवेदन करें।

20 फीसदी खेत में करें जैविक खेती

मंत्री कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि किसान अपनी भूमि का 20 प्रतिशत रकबा जैविक खेती के रूप में उपयोग करने के लिए आगे आएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बागवानी विभाग की कुछ जगहों पर अतिक्रमण होने की शिकायत मिली है। एक सप्ताह में सीमांकन करें और अतिक्रमण को हटा कर रिपोर्ट भेजें।

किसानों को प्रशस्ति-पत्र दिए

बागवानी फसलों से धान और गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों के मुकाबले अधिक कमाई होती है। इसलिए सरकार किसानों से इस तरफ ध्यान देने की अपील कर रही है। कुशवाह ने कार्यक्रम में कई किसानों को प्रोत्साहन के रूप में प्रशस्ति-पत्र तथा किट प्रदान किए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा और सोहागपुर के विधायक विजयपाल सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।

जिले में चार स्थानों पर विकसित किए जाएंगे केंद्र

उन्नत खेती से अवगत कराएंगे किसान संबल केंद्र

रहमान कुरैशी। आगर मालवा

जिले के किसानों को खेती की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराने बनाए जा रहे किसान संबल केंद्र कलेक्टर अवधेश शर्मा ने ग्राम पीलवास में जल संसाधन विभाग की कुंडालिया वृहद सिंचाई परियोजना के तहत बनाए जा रहे किसान संबल केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को कृषि लागत को कम करने तथा खेती की तकनीकी से अवगत कराने के लिए क्षेत्र के अधिक से अधिक कृषकों को जोड़ कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। कलेक्टर ने इस दौरान किसान संबल केन्द्र निर्माण कंपनी सांई संकेत के प्रोजेक्ट मैनेजर से केंद्र के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान सीईओ जिला पंचायत डीएस रणदा, उप संचालक उद्यान सुरेश राठौर, सांई संकेत कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर अमूल मोहलीकर, सिनीयर एग्रोनॉमिस्ट राजकुमार सोलंकी, मत्स्य विभाग के रामसिंह रजक, एनआरएलएम के हेमन्त रामावत व कृषक मौजूद थे।

15 हजार हेक्टेयर में बनेगा एक केंद्र

जिले में कुंडालिया वृहद सिंचाई परियोजना में एलएनटी कम्पनी द्वारा वर्तमान में चार स्थानों पर किसान संबल केन्द्र विकसित किए जाने के लिए चयन किया है। इन किसान संबल केन्द्रों का निर्माण सांई संकेत कम्पनी द्वारा किया जाएगा। यह केन्द्र 15 हजार हेक्टेयर पर एक बनाया जाएगा। वर्तमान में ग्राम पीलवास, सेमलीखेड़ी, माणा एवं लालाखेड़ी का चयन किया गया।

ताकि किसान हों सशक्त

केन्द्र का मुख्य उद्देश्य कृषकों की खेती की लागतों को कम करने के लिए प्रशिक्षित करना है। उन्हें खेती की आधुनिक तकनीकीयों से अवगत कराना है। केन्द्रों पर तकनीकी प्रशिक्षकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र के किसान नई-नई कृषि तकनीकी को अपने खेतों में अमल में लाकर खेती की लागत कम कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत राज्यमंत्री ने किया आह्वान

किसान चना-गेहूं के साथ सब्जी भी लगाएं

संवाददाता। अनूपपुर

जल की उपलब्धता का लाभ किसानों को दिलाया जाए। बेहतर सिंचाई वाले स्थानों पर किसान धान और दाल की जगह फलदार पौधे लगाएं और सब्जी की भी खेती करें। किसान सब्जी लगाकर भी दोहरा लाभ ले सकते हैं। फलदार पौधों का रोपण तथा सब्जी उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। यह बात केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायत राज्य मंत्री गिरिराज सिंह अनूपपुर जिले के प्रवास के दौरान कही। पुष्पराजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत पड़रीखार के ग्राम विचारपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटर शेड) द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण और जन चौपाल लगा लोगों की बात भी सुनी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज ने वाटर शेड योजना से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन करते हुए उन्होंने तालाबों के मेड़ पर फलदार पौधों का रोपण करने व शेष जमीन पर सब्जी उत्पादन करने के सुझाव दिए और स्थानीय ग्रामीण किसानों से चर्चा भी की।

किसानों की आजीविका पर फोकस

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में कृषि योग्य भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक गांव एक फलदार किस्म के पौधारोपण, देखभाल आदि की व्यवस्था करने पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका संवर्धन की दिशा में उन्नत प्रयास जरूरी है। उन्होंने वाटरशेड के तहत निर्मित संरचनाओं का बेहतर उपयोग कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए।

आय वाले उत्पादन को भी अपनाएं

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत पड़रीखार के ग्राम विचारपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों, कृषकों एवं स्व सहायता समूहों की महिलाओं से चर्चा की। उन्होंने समझाइश देते हुए कहा कि किसान अपने खेतों में अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाने के लिए फलदार पौधों का रोपण करें व सब्जी उत्पादन, खेत तालाब में मछली पालन की गतिविधियां अपनाकर अतिरिक्त आय के साधन बढ़ाएं।

गाय पालन पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही कुपोषित बच्चों के सुपोषण के लिए मुनगा के पौधें का रोपण करने, गाय पालन तथा जैविक खाद के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए ग्रामीणों को प्रेरित किया। उन्होंने एक गांव एक फल के तहत ग्रामीण परिवार को प्रेरित कर नवाचार करने विकास विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए।

काष्ठ कला का किया अवलोकन | जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद क्षेत्र के भ्रमण दौरान केंद्रीय मंत्री ने ग्राम कोहका पूर्व में रूरबन मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के अवलोकन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला इकाई अनूपपुर द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार गोंडी पेंटिंग, काष्ठ कला, स्थानीय उत्पाद तथा आर्गेनिक खाद की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही उत्पाद की जानकारी प्राप्त की।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- अरविंद मिश्र, संपर्क -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)